*वंचितों तक पहुंचना – बैंकिंग सेवाओं की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना**

श्री स्वामीनाथन जे.

आरबीआई, कर्नाटक की क्षेत्रीय निदेशक, श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता; नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री केवीएसएलवी प्रसाद राव; केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और एसएलबीसी कर्नाटक के संयोजक श्री के.जे. श्रीकांत; यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्र प्रमुख, बैंकों के वरिष्ठ कार्यकारी; अग्रणी ज़िला प्रबंधक (एलडीएम); ज़िला विकास प्रबंधक (डीडीएम); एलडीओ और आरबीआई के अन्य अधिकारी जो यहां मौजूद हैं। एलारिगु नमस्कारा और सभी को सुप्रभात।

सबसे पहले मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय को इस सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देता हूं, जिसका विषय था - वंचितों तक पहुंचना – बैंकिंग सेवाओं की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। यह विषय हमें याद दिलाता है कि वित्तीय समावेशन एक सतत यात्रा है। हालांकि इस यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी कुछ दूरी तय की जानी बाकी है। मैं इस सम्मेलन के लिए हुबली नामक इस स्थान का चयन करने के लिए बेंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय को भी धन्यवाद देता हूं, एक ऐसा स्थान जहां मैंने लगभग तीस वर्ष पहले भारतीय स्टेट बैंक के युवा अधिकारी के रूप में कार्य किया था – जो बुनियादी बैंकिंग की बहुत सारी पुरानी यादों को ताजा करता है जिसे हम तीन दशक पहले किया करते थे।

स्वतंत्रता के बाद समावेशी विकास की दिशा में भारत की यात्रा गरीबी को कम करने और जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य की कई पहलों द्वारा चिह्नित की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और आबादी के सभी वर्गों के लिए उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे उपायों में जबरदस्त प्रगति हुई है। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक संवृद्धि के लाभों को समाज के सभी वर्गों द्वारा साझा किया जाता है, जिसमें सीमांत समूह भी शामिल हैं, इन पहलों की आधारशिला रही है। यह आर्थिक संवृद्धि, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ एक बहुआयामी यात्रा रही है।

इस यात्रा के अपेक्षाकृत शुरुआती दिनों में, अग्रणी बैंक योजना को 1969 में संस्थागत बनाया गया था और तब से इस योजना ने उन क्षेत्रों को ऋण प्रवाह बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया है जिन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है और देश की वंचित आबादी के लिए, सभी स्तरों पर जैसे ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है।

अपनी स्थापना के बाद से आधी सदी से अधिक समय में, यह योजना देश के विकास एजेंडे के अनुरूप विकसित हुई है। अग्रणी बैंक योजना अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी तंत्र के बीच सभी स्तरों पर समन्वित दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इस समन्वित दृष्टिकोण से बैंकिंग पहुंच के विस्तार और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रवाह में सुधार के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं।

हाल ही में इसने देश के हर जिले को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से एसएलबीसी के साथ डिजिटल भुगतान के विस्तार का भी नेतृत्व किया है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि 354 जिले अब डिजिटल रूप से सक्षम हो गए हैं। कर्नाटक सहित दस राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पहल के तहत जिलों का 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है।

वास्तव में, अग्रणी बैंक योजना परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकती है। एलडीएम, डीडीएम और एलडीओ के रूप में, आप वे स्तंभ हैं जिन पर यह योजना टिकी हुई है, जो जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं और ऋण पहुंच का विस्तार करने में आपके प्रयास निस्संदेह सभी शामिल लोगों के लिए अत्यधिक संतुष्टि लाएंगे। तेलंगाना में एसएलबीसी के संयोजक के रूप में कार्य करने के बाद, मैं व्यक्तिगत रूप से उस गहन तृप्ति को समझ सकता हूं जो

* 20 सितंबर 2024 को हुबली में अग्रणी जिला प्रबंधकों और जिला विकास प्रबंधकों के सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे का मुख्य भाषण।

एलबीएस मंचों के माध्यम से लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अंतर लाने से आती है।

हमारे सामने एक आम सवाल यह है कि क्या हम पर्याप्त कर रहे हैं? अभी और कितना किया जाना बाकी है? 2021 में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-सूचकांक) पेश किया, जो तीन प्रमुख आयामों में 97 संकेतकों में प्रगति का पता लगाता है: (i) पहुंच (ii) उपयोग (iii) गुणवत्ता। सूचकांक जो मार्च 2021 में 53.9 पर था, अब मार्च 2024 के लिए 64.2 पर है, जो आप सभी द्वारा किए गए प्रयासों का सबूत है।

भारत ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक 'पहुंच' बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, यहां तक कि सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंच बनाई है। हालांकि, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अभी भी काफी कुछ बाकी है। इसके लिए 'उपयोग' को बढ़ावा देने और सेवाओं की 'गुणवत्ता' में सुधार करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधकों और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों की भूमिका अपरिहार्य है।

इस संदर्भ में, मैं कुछ प्रमुख अपेक्षाओं को रेखांकित करना चाहूंगा।

अपने जिले को अच्छी तरह से जानें

सबसे पहले, यह जरूरी है कि आप अपने संबंधित जिलों की गहरी समझ विकसित करें- इसलिए, आपको वास्तव में 'अपने जिलों को अच्छी तरह से जानना' चाहिए। यह ज्ञान व्यापक जिला प्रोफाइल के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। इस तरह के प्रोफाइल में विस्तृत जनसांख्यिकीय जानकारी, कृषि रुझान, बैंकिंग पैठ और गतिविधियां, औद्योगिक प्रोफाइल और वार्षिक ऋण योजनाओं (एसीपी) के तहत विभिन्न प्रदर्शन मैट्रिक्स शामिल हो सकते हैं।

अपने जिलों को अच्छी तरह से जानने के बाद, आप आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय ऋण आवश्यकताओं और क्रेडिट पहुंच में बाधाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और फील्ड सर्वेक्षणों का लाभ उठा सकते हैं। अपने जिले की समग्र समझ आपको वित्तीय समावेशन में अंतराल की पहचान करने, विभिन्न क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने और हस्तक्षेप के लिए लक्षित कार्यनीतियों को डिजाइन करने में सक्षम बनाएगी। यह आपको अपने जिलों के विभिन्न मुद्दों के मूल कारणों की पहचान करने में भी मदद करेगा। अपने जिलों के प्रति अभ्यस्त रहकर, आप एसएलबीसी को अमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं, लक्षित और प्रभावी ऋण योजनाओं के निर्माण को सक्षम कर सकते हैं, और सतत आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

लक्षित और प्रभावी क्रेडिट योजनाओं का निर्माण, नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण

दूसरे, अपने जिले की अपनी मजबूत समझ के आधार पर, ऋण योजना के निर्माण, निगरानी और कार्यान्वयन को एकदम छोटे से ऊपर दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

डीडीएम द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के अंतर्गत ऋण संभाव्यता का मानचित्रण करने के साथ राज्य के सभी जिलों के लिए संभाव्यता संबद्ध ऋण योजनाएं (पीएलपी) तैयार करके ऋण योजना का प्रमुख चरण तैयार किया जाता है। पीएलपी तैयार करने में ब्लॉक-वार और क्षेत्र-वार क्षमता का आकलन शामिल है। एलडीएम जमीनी स्तर पर ब्लॉक ऋण योजनाओं की अवधारणा करते हैं जो जिला ऋण योजनाओं में समाहित होती हैं, अंततः व्यापक राज्य-स्तरीय वार्षिक ऋण योजना बनाई जाती है। ऐसा करते समय, ऋण संवितरण के लिए लक्ष्य निर्धारण को यथार्थवादी होने के साथ-साथ आकांक्षात्मक होना चाहिए। एलडीएम को अपने प्रभार के तहत ब्लॉकों और जिलों के लिए ऋण योजनाओं को औपचारिक रूप देते समय संभाव्यता संबद्ध योजनाओं में इंगित ऋण देने की गुंजाइश के साथ-साथ ऋण संवितरण में उपलब्धि के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए।

अंतराल को पाटना

तीसरा, हमें शेष कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। हालांकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण में समय के साथ प्रगति हुई है, फिर भी विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में महत्वपूर्ण काम किया जाना बाकी है। इसी प्रकार, लगभग आधे स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को औपचारिक ऋण से जोड़ा जाना बाकी है, और छोटे और सीमांत किसानों के एक बड़े हिस्से की अभी भी बैंक वित्तपोषण तक पहुंच नहीं है।

इसलिए, हमें पीएलपी के साथ-साथ ब्लॉक और जिला-स्तरीय ऋण कार्यनीतियों में इन खंडों की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

एमएसएमई भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में प्रमुख आवश्यकताओं में से एक महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि है। विभिन्न अध्ययनों[1] से पता चला है कि कम से कम एक महिला संस्थापक वाले व्यवसायों में अधिक समावेशी कार्य संस्कृति है, पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं को रोजगार देते हैं और अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। हालांकि, 20 प्रतिशत से कम एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व में हैं। महिला उद्यमियों को अक्सर बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि धन तक सीमित पहुंच, सामाजिक बाधाएं और किफायती वित्त प्राप्त करने में चुनौतियां।

इसलिए लैंगिक अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पर, इसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों और महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए अनुरूप बैंकिंग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देकर संबोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इन अवसरों के बारे में संभावित महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

वित्तीय साक्षरता

चौथे, हमें वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। आपूर्ति-पक्ष को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन समग्र वित्तीय समावेशन के लिए मांग-पक्ष की पहल की भी आवश्यकता है। वित्तीय साक्षरता इसका एक मूल तत्व है। यह केवल पहुंच के बारे में नहीं है, यह व्यक्तियों को सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। वित्तीय साक्षरता लोगों की व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट और निवेश सहित विभिन्न वित्तीय कौशल को समझने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है।

जनता को उनके लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, चाहे वह बीमा और पेंशन योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा उत्पाद हों, जो उनके जोखिमों को कवर करेंगे या महत्वपूर्ण सब्सिडी वाले ऋण उत्पाद जो उन्हें उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। डिजिटल लेनदेन करने में जनता के विश्वास में सुधार के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बैंकों को फिनटेक को व्यापक रूप से अपनाने के लिए रास्ते तलाशने, निर्बाध और घर्षण रहित ऋण प्रदान करने में सक्षम करेगा।

ब्लॉक स्तर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और बैंकों की वित्तीय सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (सीएफएल) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का संवर्धन किया जा रहा है। सीएफएल की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है, 2,421 सीएफएल अब देश के लगभग हर ब्लॉक में काम कर रहे हैं। अकेले कर्नाटक में ही 79 सीएफएल और 177 वित्तीय साक्षरता केन्द्र बुनियादी स्तर पर वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। एलडीएम को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि एफएलसी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करें, सीएफएल का समर्थन करें, सीएफएल शिविरों में भाग लें, और इन शिविरों के उचित संचालन की देखरेख करते हुए वित्तीय सेवाओं के संयोजन को सुविधाजनक बनाएं।

अंत में, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, अनुकरणीय मानक स्थापित करें और विकासात्मक गतिविधियों में अग्रणी बनें जिससे आपके जिलों और कर्नाटक राज्य की निरंतर प्रगति सुनिश्चित हो।

जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय रिज़र्व बैंक इस वर्ष अपनी स्थापना के 90 वर्ष मना रहा है। अगले दशक की ओर देखें तो, आरबीआई@100 की ओर हमारी यात्रा, हमने रिज़र्व बैंक को ग्लोबल साउथ के एक मॉडल केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यनीतियाँ तैयार की हैं। हमारे प्रमुख उद्देश्यों में से एक समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाकर वित्तीय समावेशन को गहरा करना है। मैं आप में से प्रत्येक से आग्रह करता हूं कि समावेशी

[1] जेटली, एस., थंगाल्लापल्ली, एल.एस., और माइक्रोसेव. (2022)। भारत में महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता प्रदान करने के संबंध में। नीति आयोग में, www.microsave.net [रिपोर्ट]। https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Decoding-Government-Support-to-Women-Entrepreneurs-in-India.pdf (अंतिम बार 16 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया)

विकास में योगदान देकर, यह सुनिश्चित करके कि आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में कोई भी पीछे न रहे, और जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर इस संकल्पना को साकार करने में हमारा सक्रिय समर्थन करें।

मैं आप सबसे राष्ट्रकवि कुवेम्पु (उनके महाकाव्य कार्य "मालेगाल्ली मदुमगाऊ") के एक उद्धरण के साथ विदा लेना चाहूँगा:

ಇಲ್ಲಿಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ

इल्ली यारू मुख्यरल्ला

यहां कोई भी कीमती नहीं है

ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ

यारू मुख्यरल्ला

यहां कोई भी महत्वहीन नहीं है

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅರ್ಥ

इल्ली एललकु इडे अरथा

यहां हर चीज का महत्व है

ಯಾಮದೂ ಅಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ

यवुडु अल्ला व्यर्था

कुछ भी बेकार नहीं है

ನೀರಿಲ್ಲಮೂ ತೀರ್ಥ!

नीरेलेवू तीरथा!

सभी जल पवित्र है!

आज की सभा के संदर्भ में, इसका अर्थ होगा: लोगों के सभी समूह समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें आर्थिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए; वित्तीय समावेशन के लिए किया गया हर प्रयास सार्थक है और कुछ भी बेकार नहीं होता है।

इसी के साथ, मैं आप में से प्रत्येक को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद!